क.

श्री दिग्विजय सीमेंट कं.लिमिटेड।और ओआरएस।

वी.

राजस्थान राज्य और ओ. आर. एस.

17 दिसंबर, 1999

बी. [एस. पी. भरुचा, बी. एन. किरपाल, वी. एन. खरे, डी. पी. मोहपात्र,

एन. संतोश हेगड़े, जे. जे.]

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956-धारा 8 (5)-राजस्थान राज्य द्वारा 12 मार्च, 1997 को जारी अधिसूचना-बिक्री कर की दर में कमी

क.

राजस्थान में किसी भी व्यापारी द्वारा सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री पर 4 प्रतिशत तक-अधिनियम की धारा 8 (4) में प्रदान किए गए फॉर्म सी में घोषणा या फॉर्म डी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के साथ वितरण-वैध कानूनी और संवैधानिक।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 301 और 303-बिक्री में कमी

डी.

सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री और फॉर्म सी घोषणा और फॉर्म डी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कर की दर 4 प्रतिशत-संवैधानिक वैधता

आयोजित, मूल्यवान और संवैधानिक।याचिकाकर्ता 1 और 3 सीमेंट कंपनियाँ थीं, जिनकी विनिर्माण ई इकाइयाँ गुजरात राज्य में थीं।उनके द्वारा निर्मित सीमेंट गुजरात और अन्य जगहों पर बेचा जाता था।

राजस्थान राज्य ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (5) के तहत, 8 जनवरी 1990 और 27 जनवरी 1990 की अधिसूचना जारी की, जिसका प्रभाव राजस्थान से एफ डीलरों द्वारा सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर को घटाकर 7 प्रतिशत करने पर पड़ा, भले ही स्थानीय बिक्री के संबंध में कर

16 % .इन अधिसूचनाओं को उपरोक्त कंपनियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी।इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान राजस्थान राज्य द्वारा 7 मार्च 1994 को एक और अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया था, और फॉर्म सी घोषणा या फॉर्म डी भी प्रस्तुत किया गया था।

जी.

राजस्थान में विक्रेताओं द्वारा प्रमाण पत्र जिन्होंने अंतर-राज्यीय बिक्री को प्रभावित किया था।उपरोक्त रिट याचिका में संशोधन किया गया और 7 मार्च, 1994 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि बिक्री कर में इस तरह की कमी के परिणामस्वरूप राजस्थान से सीमेंट पड़ोसी राज्यों में बहुत सस्ता हो गया।



गुजरात जैसे राज्य और इससे ए निर्मित सीमेंट की स्थानीय बिक्री प्रभावित हुई।

गुजरात में स्थानीय बिक्री पर बिक्री कर की उच्च दर के कारण गुजरात में याचिकाकर्ताओं द्वारा।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कर की दर में इस तरह की कमी संविधान के भाग XIII में निहित योजना के विपरीत थी और इसलिए इसे निरस्त किया जा सकता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसकी सुनवाई की गई और 5 मार्च 1997 को फैसला सुरक्षित रखा गया।

12 मार्च 1997 को राजस्थान राज्य ने धारा 8 (5) के तहत एक और अधिसूचना जारी की जो पहले की अधिसूचना के समान थी जिसमें उसने उस राज्य के किसी भी व्यापारी द्वारा सीमेंट की अंतर-राज्य बिक्री पर बिक्री कर की दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया और धारा 8 (4) द्वारा आवश्यक फॉर्म सी घोषणा या फॉर्म डी प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

इस न्यायालय ने 21 मार्च 1997 को याचिकाकर्ताओं की दीवानी अपील को स्वीकार कर लिया और 8 जनवरी 1990,27 जनवरी 1990 और 7 मार्च 1994 की पिछली अधिसूचना को रद्द कर दिया।न्यायालय ने श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी और ए. एन. आर. में फैसला सुनाया।वी.राजस्थान राज्य, [1994] 5 एस. सी. सी. 406 कि कर की दर को 16 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने से राजस्थान से गुजरात में सीमेंट की बढ़ती प्रेषण और गुजरात में निर्मित सीमेंट की स्थानीय बिक्री में कमी का प्रभाव पड़ा, और इसके परिणामस्वरूप व्यापार के मुक्त ई प्रवाह पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।अदालत ने आगे कहा कि फॉर्म सी घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता के साथ वितरण अधिसूचनाओं का कर के भुगतान की चोरी को सुविधाजनक बनाने का प्रभाव था और इसलिए, अध्याय XIII में निहित संवैधानिक योजना का उल्लंघन था।

याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका पर एफ. 26 नवंबर, 1998 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की गई और इसने कहा कि 21 मार्च 1997 को न्यायालय के फैसले द्वारा अनुच्छेद 301 और 303 का उल्लंघन करते हुए इसी तरह की पिछली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था और इस फैसले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।

नतीजतन यह मामला जी के लिए संवैधानिक पीठ के समक्ष आया

निपटान।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि

( i) धारा 8 (5) के तहत वह विवादित अधिसूचना इसके साथ असंगत थी

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में निहित विधायी नीति और एच

पी.

1 430

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

एक अस्वीकार्यः

( (ii) फॉर्म सी प्रस्तुत करने की आवश्यकता का वितरण।

घोषणा या फॉर्म डी प्रमाणपत्र संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 का उल्लंघन था।

संविधान ने माल की मुक्त आवाजाही को रोका या बाधित किया

एक राज्य से दूसरे राज्यः

( (iii) इससे कर चोरी की सुविधा हुई और इसकी अनुमति नहीं थी और

( (iv) इसे सार्वजनिक हित में नहीं माना जा सकता है जैसा कि विचार किया गया है।

धारा 8 (5)।

प्रत्यर्थियों ने यह प्रस्तुत करते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि

एस.

विवादित अधिसूचना जनहित में जारी की गई थी, यह उल्लंघनकारी नहीं थी

संविधान के भाग XIII का, और यह कि इस न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांकित है

21 मार्च, 1997 सही कानून निर्धारित नहीं करता है और इसकी आवश्यकता है

पुनर्विचार किया गया।

रिट याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने

डी.

अवधारित 1. एन. के. नटराज मुदलियार के फैसले ने न केवल इसे बरकरार रखा है

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 (2), (2 ए) और (5) की वैधता लेकिन

यह पाया गया कि धारा 8 की उप-धारा (5) राज्य सरकार को अधिकृत करती है।

सार्वजनिक हित में कर की दर को माफ करना या कम करना, चाहे कुछ भी हो

ई धारा 8 में निहित है।इसलिए, धारा 8 (5) के तहत शक्ति के प्रयोग को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, सिवाय इस आधार के कि ऐसी शक्ति के पास नहीं है

जनहित में प्रयोग किया गया।[ 444 - डी]

मद्रास राज्य बनाम।एन. के. नटराज मुदलियार, [1968] 3 एस. सी. आर. 829, ने भरोसा किया

पर।

च

2. धारा 8 (5) को वैध माना गया है और इसके दायरे को समझाया गया है

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय में यह प्रावधान है कि अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में

राज्य में अपना व्यवसाय स्थान रखने वाले किसी भी व्यापारी द्वारा कुछ प्रकार की वस्तुएँ,

कोई कर देय नहीं होगा या कर की गणना उनसे कम दरों पर की जाएगी।

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट।[ 446 - सी]

जी.

तमिलनाडु राज्य और अन्य।वी.सीतालक्ष्मी मिल्स और ओआरएस।, [ 1974 ] 4 एससीसी

408 ; ग्वालियर रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी.& डब्ल्यूवीजी।कं. लिमिटेड बनाम।आसिस्टेंट।बिक्री आयुक्त

क.

कर, [1974] 4 एस. सी. सी. 98 और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड बनाम।पंजाब राज्य और

एन. आर., [ 1990 ] 3 एस. सी. सी. 87, पर भरोसा किया।

3. अंतर-राज्य बिक्री कर की दर को छूट देने या कम करने की शक्ति श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।

एच.

लिमिटेड।वी.राज्य 431

कुछ प्रकार की वस्तुओं पर, जैसे कि तत्काल मामले में सीमेंट का उपयोग करना पड़ता है

जब राज्य सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा जनहित में करना आवश्यक है।[ 446 - डी]

4. अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की उच्च दर जो प्रचलित थी

इसके परिणामस्वरूप विनिर्माण इकाइयों ने राजस्थान राज्य में बिना किसी कर का भुगतान किए बी एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमेंट की शाखा हस्तांतरण का सहारा लिया।[ 446 - जी]5. राजस्थान राज्य के भीतर सीमेंट की मांग के साथ

सीमित, राजस्थान राज्य से सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री को प्रोत्साहित करना अनिवार्य हो गया।अंतर-राज्यीय बिक्री कर की दर को कम करने में सुविधा हुई

उच्च कर वापसी में और उद्योग में काम करना जारी है।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त अधिसूचना जारी करना जनहित में था जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (5) द्वारा परिकल्पित है।[ 447 - ए-बी]

6. केवल इसलिए कि गुजरात राज्य में सीमेंट की बिक्री पर कर की स्थानीय दर डी राजस्थान से बेचे जाने वाले सीमेंट पर अंतर-राज्य बिक्री कर से अधिक थी, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि विवादित अधिसूचना

एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की मुक्त आवाजाही को रोका या बाधित किया।वास्तव में, आक्षेपित अधिसूचना का विपरीत प्रभाव पड़ा।इसने राजस्थान से अन्य राज्यों में सीमेंट की आवाजाही को बढ़ाया।ऐसा नहीं है कि विवादित अधिसूचना ने एक बाधा उत्पन्न की है जिसका माल की मुक्त आवाजाही में बाधा डालने का प्रभाव हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर, बिक्री कर बाधा को कम कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप अंतर-राज्य व्यापार पर मात्रा में वृद्धि हुई थी।[ 444 - सी-डी]7. धारा 8 (5) के तहत जारी अधिसूचना का गैर-बाध्यकारी खंड को देखते हुए अति-प्रभावी प्रभाव हो सकता है।फॉर्म सी और फॉर्म डी को राजस्थान के डीलरों द्वारा एफ पंजीकृत डीलर या राजस्थान के बाहर किसी सरकारी विभाग को अंतर-राज्यीय बिक्री के प्रमाण के रूप में माना जाता है।विवादित अधिसूचना में विक्रेता को बिल या नकद ज्ञापन में खरीदार का नाम और पता दर्ज करना होता है जिसे उसे अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में जारी करना होता है और विक्रेता को यह साबित करना होता है कि लेन-देन अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति का था।जी व्यापारी के लिए बिल या नकद ज्ञापन में खरीदार का नाम और पता दर्ज करना अनिवार्य बनाकर प्रपत्र सी और प्रपत्र डी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के प्रतिस्थापन का कर चोरी को सुविधाजनक बनाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।राजस्थान राज्य का अनुभव रहा है कि इस तरह की अधिसूचनाओं के जारी होने से सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री में इसके कर राजस्व में वृद्धि हुई है।[ 447 - ई-जी]8. एच 432 द्वारा अंतर-राज्यीय बिक्री कर की दर में परिवर्तन की स्पष्ट रूप से अनुमति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी. पी.5 एस सी आर।

धारा 8 (5) जिसकी वैधता को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया है।यह निष्कर्ष कि अंतर-राज्य बिक्री कर की दर में भिन्नता, जो एक स्थानीय वरीयता पैदा करती है, संविधान के भाग XIII में योजना के विपरीत है, सही नहीं है।दूसरी ओर छूट देने की शक्ति को बरकरार रखा गया है बशर्ते इसका दुरुपयोग न किया गया हो।[ 448 - डी-ई; 448-एच; 449-ए] बी 9।1957 से पहले, धारा 8 (5) ने केंद्र सरकार को केंद्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम 1957 के साथ सार्वजनिक हित में बिक्री कर की दर को कम करने की शक्ति दी थी, संसद ने यह शक्ति केंद्र के बजाय राज्य सरकारों को प्रदान की थी।

सरकार।इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अधिनियम की धारा 8 (5) में उल्लिखित जनहित में निश्चित रूप से राज्य का जनहित शामिल होगा।

एस.

चिंतित हैं।यदि कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप उद्योग के साथ-साथ चूना पत्थर के खनन में वृद्धि होती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिसूचना जनहित में जारी नहीं की गई थी।[ 449 - डी-एफ]

10. तत्काल मामले में, डी अधिसूचना का लाभ उठाने की शर्त यह है कि बिल या नकद ज्ञापन में खरीदार का नाम और पूरा पता बताना होगा और इसके परिणामस्वरूप यह साबित करने का बोझ कि लेनदेन अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति का था, विक्रेता पर है।अतः मूल्यांकन के समय, जो व्यापारी उक्त अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे राज्य के बाहर खरीदार की पहचान स्थापित करनी होगी और बदले में यह भी साबित करना होगा कि अंतर-राज्यीय बिक्री हुई है।ई कर जो एकत्र किया जाता है, उस राज्य को आवंटित किया जाता है जहाँ से परिवहन होता है।

माल शुरू होता है।इसलिए, इस सवाल को कि क्या कर की चोरी होती है, उस राज्य के लिए प्रासंगिकता के साथ देखा जाना चाहिए।यदि कर में कमी के परिणामस्वरूप अधिक लोगों को उस राज्य को कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करके कर संग्रह में वृद्धि होती है तो यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 301 का उल्लंघन किया गया है।[ 450 - ए-सी]

च

11. यह विचार कि अधिसूचना की आवश्यकता के साथ वितरण

प्रपत्र सी में घोषणा प्रस्तुत करने से कर के भुगतान की चोरी को सुविधाजनक बनाने का प्रभाव पड़ा और यह अध्याय XIII में निहित संवैधानिक प्रावधानों की योजना का उल्लंघन था जिसकी सदस्यता नहीं ली जा सकती है।केवल यह तथ्य कि गुजरात में सीमेंट की स्थानीय बिक्री प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई होगी, जी के परिणामस्वरूप विवादित अधिसूचना को व्यापार के मुक्त प्रवाह को प्रभावित करने और अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।उक्त प्रावधान एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही से संबंधित है और जहां तक तत्काल मामले का संबंध है, कर में कमी के साथ, आवाजाही बढ़ी है, बल्कि कम हो गई है।राजस्थान राज्य द्वारा 12 मार्च 1997 को जारी अधिसूचना की वैधता को तदनुसार बरकरार रखा गया है।

एच.

( 434 - एफ; 450-जी; 451-बी] श्री दिग्विजय स्मारक कंपनी।

लिमिटेड।वी.राज्य [किरपाल, जे.] 433 नागरिक मूल न्यायनिर्णयःरिट याचिका (सी) सं. 366/1997 ए (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं के लिए (ग) नं. शांति भूषण, सुनील गुप्ता, आर. पी.

संघी, पुनीत त्यागी, नरेंद्र शर्मा और आर. पी. सिंह।

बी उत्तरदाताओं के लिए राजस्थान राज्य बी. सेन, सुशील कुमार जैन, ए.

मिश्रा, सुश्री मधुरिमा तातिया और अरुणेश्वर गुप्ता।

डब्ल्यू. पी. में प्रत्यर्थी संख्या 4 (ग) नं. 366/97 आर. एफ. नरीमन, प्रदीप अग्रवाल,

एम. एल. पटोदी और सुश्री प्रतिभा जैन।

एस.

डब्ल्यू. पी. में प्रत्यर्थी संख्या 5 (ग) सं. 366/97 प्रदीप अग्रवाल और

सुश्री प्रतिभा जैन।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

किरपाल, जे. इस रिट याचिका में चुनौती अधिसूचना डी के लिए है

राजस्थान राज्य द्वारा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत दिनांक 12 मार्च, 1997 को जारी किया गया [संक्षेप में 'अधिनियम'] जिसके तहत उसने उस राज्य के किसी भी व्यापारी द्वारा सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर की दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया और अधिनियम की धारा 8 (4) द्वारा अनुध्यात प्रपत्र-सी में घोषणा या प्रपत्र-डी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

ई.

श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड और मैसर्स गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, याचिकाकर्ता नं।1 और यहाँ 3, सीमेंट का निर्माण करते हैं और गुजरात राज्य में उनकी विनिर्माण इकाइयाँ हैं।उनके द्वारा निर्मित सीमेंट गुजरात और अन्य जगहों पर बेचा जाता है।राजस्थान राज्य ने 8 जनवरी, 1990 और 27 जून, 1990 की धारा 8 (5) अधिसूचनाओं के तहत जारी किया था, जिसका प्रभाव एफ

राजस्थान के विक्रेताओं द्वारा अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर को घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया, भले ही स्थानीय बिक्री के संबंध में कर 16 प्रतिशत था।इन अधिसूचनाओं को याचिकाकर्ताओं द्वारा फरवरी 1994 में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी।इस याचिका के लंबित रहने के दौरान राजस्थान राज्य ने 7 मार्च, 1994 को अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर को घटाकर 4 प्रतिशत जी कर दिया गया और राजस्थान में विक्रेताओं द्वारा प्रपत्र-सी में घोषणा या प्रपत्र-डी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने अंतर-राज्यीय बिक्री को प्रभावित किया हो।

1

7 मार्च, 1994 की इस अधिसूचना में उपरोक्त रिट याचिका में संशोधन करके

उसे भी चुनौती दी गई।

उपरोक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि एच 434 के रूप में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

बिक्री कर में इस तरह की कमी के परिणामस्वरूप, राजस्थान से सीमेंट गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों में बहुत सस्ता हो गया और इसने गुजरात में याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित सीमेंट की स्थानीय बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाला क्योंकि उस राज्य के भीतर स्थानीय बिक्री पर बिक्री कर की उच्च दर थी।इस तरह

+

यह तर्क दिया गया कि कर की दर में कमी संविधान के भाग XIII में निहित योजना के विपरीत थी और इसे निरस्त किया जा सकता था।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।इसके बाद ए

इस अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।अनुमति दी गई और 1997 की सिविल अपील संख्या 2145 की सुनवाई की गई और 5 मार्च, 1997 को निर्णय सुरक्षित रखा गया।इसके बाद 12 मार्च, 1997 को राजस्थान राज्य ने धारा 8 (5) के तहत विवादित अधिसूचना जारी की जो पहले की अधिसूचनाओं के समान थी और सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर को जारी रखा।

1

॰

4 प्रतिशत की कम दर पर।12 मार्च, 1997 की यह अधिसूचना 31 मार्च, 1998 तक लागू रहने वाली थी।

21 मार्च, 1997 को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया।

डी और 8 जनवरी, 1990,27 जून, 1990 और 7 मार्च, 1994 की पिछली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था।उक्त निर्णय में श्री दिग्विजय के रूप में सूचित किया गया है

सीमेंट कंपनी और एन. आर.वी.राजस्थान राज्य और अन्य।, [ 1994 ] 5 एससीसी 406, यह था

उन्होंने कहा कि कर की दर को 16 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रभाव वृद्धि पर पड़ा

राजस्थान से गुजरात में सीमेंट का प्रेषण और स्थानीय स्तर पर सीमेंट की मात्रा में कमी

गुजरात में निर्मित सीमेंट की बिक्री और उक्त अधिसूचनाएँ,

ई को व्यापार के मुक्त प्रवाह पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए खराब माना गया था।यह भी माना गया कि अधिसूचनाएँ

प्रपत्र-सी में घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता ने सुविधा प्रदान करने का प्रभाव डाला

कर के भुगतान की चोरी और इसलिए, योजना का उल्लंघन था

आई.

अध्याय XIII में निहित संवैधानिक प्रावधान।

च

वर्तमान रिट याचिका में 12 वीं की अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

मार्च, 1997, जो पहले की अपील में विषय नहीं था, पर

जिन आधारों को इस न्यायालय ने 21 तारीख के अपने उपरोक्त निर्णय में समर्थन दिया

मार्च, 1997।

26 नवंबर, 1998 को इस याचिका पर तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।

जी.

न्यायाधीश।यह देखा गया कि श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के मामले (ऊपर) में इसी तरह की पिछली अधिसूचनाओं को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वे संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 का उल्लंघन कर रही थीं।पीठ ने कहा कि उपरोक्त निर्णय पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उक्त एच अधिसूचना पर अनुच्छेद 301 और 303 के लागू होने के संबंध में।इस तरह इस याचिका पर इस पीठ द्वारा सुनवाई की गई है।

श्री दिग्विजय सीमेंट कं.लिमिटेड।वी.राज्य (किरपाल, जे.) अधिनियम की धारा 435 धारा 8, जहां तक यह इस ए के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है

मामला इस प्रकार हैः

8. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर की दरें-( 1 ) प्रत्येक विक्रेता, जो अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान

( (क) सरकार को कोई वस्तु बेचता है; या

( ख) सरकारी वस्तुओं के अलावा किसी अन्य पंजीकृत विक्रेता को बेचता है।

उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरण;

इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो होगा [प्रति वर्ष चार

उनके कारोबार का प्रतिशत।

( 2 ) घोषित वस्तुओं के मामले में जहां तक अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री से संबंधित कारोबार या उसके किसी हिस्से का संबंध है, किसी भी व्यापारी द्वारा उसके कारोबार पर देय कर की गणना (डी दर के दोगुने पर) उचित राज्य के भीतर ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लागू होगी; और

( ख) घोषित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के मामले में, गणना दस प्रतिशत की दर से या उपयुक्त राज्य के भीतर ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लागू दर पर की जाएगी।

जो भी अधिक हो;

और ऐसी कोई गणना करने के उद्देश्य से ऐसा कोई भी विक्रेता बिक्री कर कानून या उपयुक्त राज्य के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यापारी समझा जाएगा, भले ही वह वास्तव में उस कानून के तहत इतना उत्तरदायी न हो।

च

( 2 - क) धारा 6 की उप-धारा (1-क) या इस धारा की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत एक व्यापारी द्वारा अपने कारोबार पर देय कर, जहां तक कि कारोबार या उसका कोई हिस्सा किसी ऐसी वस्तु की बिक्री से संबंधित है, या जिसकी खरीद, यथास्थिति, उपयुक्त राज्य की बिक्री कर कानून जी के तहत, आम तौर पर कर से छूट प्राप्त है या आम तौर पर उस दर से कर के अधीन है जो (चार प्रतिशत) (चाहे कर या शुल्क कहा जाए या किसी अन्य नाम से) से कम हो, शून्य या शून्य होगा।

मामला हो सकता है, कम दर पर गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण-- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए एक बिक्री या खरीद एच

{ 436

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए. किसी भी वस्तु को उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के तहत आम तौर पर कर से मुक्त नहीं माना जाएगा, अगर उस कानून के तहत ऐसी वस्तु की बिक्री या खरीद को केवल निर्दिष्ट नियमों में छूट दी गई है।

परिस्थितियों या निर्दिष्ट शर्तों के तहत या कर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर निर्दिष्ट स्तर पर या माल के कारोबार के संदर्भ में नहीं बल्कि अन्यथा लगाया जाता है।

( 3 ) उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट माल -

'

( अ) छोड़ दिया गया

( बी) * * * * * पंजीकृत विक्रेता के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सामान हैं, जो सामान को खरीदते हैं

एस.

उसके द्वारा पुनर्विक्रय के लिए या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, उसके द्वारा बिक्री के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में या खनन में या बिजली के उत्पादन या वितरण में या किसी अन्य रूप में उपयोग के लिए

शक्ति;

डी.

( ग), माल की खरीद करने वाले पंजीकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र या पंजीकरण में निर्दिष्ट कंटेनर या अन्य सामग्री हैं, जो बिक्री के लिए माल की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनर या सामग्री हैं;

( घ) पात्र या अन्य सामग्री हैं जिनका उपयोग किसी भी वस्तु की पैकिंग के लिए किया जाता है।

ई.

प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट माल या माल के वर्ग

खंड (बी) में निर्दिष्ट पंजीकरण या प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किसी भी पात्र या अन्य सामग्री की पैकिंग के लिए

खंड (ग) में निर्दिष्ट पंजीकरण।

( 4 ) उप-धारा (1) के प्रावधान किसी भी बिक्री पर लागू नहीं होंगे।

च

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की प्रक्रिया जब तक कि माल बेचने वाला विक्रेता निर्धारित तरीके से निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है।

( क) उस पंजीकृत विक्रेता द्वारा विधिवत भरी और हस्ताक्षरित एक घोषणा जिसमें निर्धारित विवरण शामिल हों, जिसे माल बेचा जाता है।

जी.

निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में; या

क.

( ख) यदि माल सरकार को बेचा जाता है, जो एक पंजीकृत विक्रेता नहीं है, तो निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा और हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

सरकार के विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा;

बशर्ते कि खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा प्रस्तुत की गई हो

एच.

ए} श्री दिग्विजय समारोह कं.लिमिटेड।वी.राज्य [के. आई. आर. पी. ए. एल., जे.] 437 निर्धारित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जब कोई प्राधिकारी पर्याप्त कारण के लिए अनुमति दे।

( 5 ) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसमें निर्दिष्ट की जाएं, बी को निर्देश दे सकती है कि (ए) इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यापारी द्वारा, जो राज्य में अपना व्यवसाय स्थान रखता है, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान, अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली किसी भी ऐसी वस्तु या माल के वर्गों के व्यवसाय के किसी भी स्थान से की गई बिक्री के संबंध में कोई कर देय नहीं होगा, या यह कि ऐसी बिक्री पर कर की गणना उप-राजपत्र में निर्दिष्ट दरों से इतनी कम दरों पर नहीं की जाएगी।

धारा (1) या उप-धारा (2) जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया जा सकता है;

( (ख) अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में, राज्य में अपना व्यवसाय स्थान रखने वाले किसी व्यापारी द्वारा या ऐसे विक्रेताओं के किसी वर्ग द्वारा, जो अधिसूचना में किसी व्यक्ति को या अधिसूचना में निर्दिष्ट व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, वस्तुओं की सभी बिक्री या वस्तुओं के ऐसे वर्गों की बिक्री के संबंध में, जो अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं होगा या ऐसी बिक्री पर कर की गणना निम्न में निर्दिष्ट दरों से कम दरों पर की जाएगी।

उप-धारा (1) या उप-धारा (2) जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया जा सकता है।

विवादित अधिसूचना धारा की उप-धारा (5) के तहत जारी की गई है।यह उप-धारा जब मूल रूप से अधिनियमित की गई थी तो निम्नानुसार थीः

च

" ( 5 ) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह निर्देश दे सकती है कि ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्गों के

संबंध में, जिनका उल्लेख अधिसूचना में किया जा सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह जी को उचित समझे, इस अधिनियम के तहत कोई कर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अपना व्यवसाय स्थान रखने वाले किसी भी व्यापारी द्वारा अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी ऐसी वस्तु के व्यापार के स्थान से उसके द्वारा की गई बिक्री के संबंध में देय नहीं होगा या ऐसी बिक्री पर कर की गणना उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दरों से इतनी कम दरों पर की जाएगी, जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाए।

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1999] एस. पी.5 एस सी आर।

4 438

उप-धारा (5) में 'राज्य सरकार' और 'राज्य' शब्दों को केंद्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम No.16) की धारा 2 द्वारा क्रमशः 'केंद्र सरकार' और 'किसी भी केंद्र शासित प्रदेश' के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।इस प्रकार इस संशोधन ने राज्य सरकार को (संशोधित प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के स्थान पर), यदि वह चाहे तो, किसी भी वस्तु या माल के वर्ग को केंद्रीय बिक्री कर से छूट देने या निर्धारित करने में सक्षम बनाया।

इसके लिए कर की कम दर।संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन का खंड 4

1957 का विधेयक इस प्रकार हैः

" संयोग से, धारा 8 (5) में संशोधन करने की मांग की गई है ताकि इसे सक्षम किया जा सके।

एस.

एक राज्य सरकार, यदि वह चाहती है, किसी भी वस्तु या वर्ग को छूट देने के लिए

अंतर-राज्य बिक्री कर से माल "।

अपने वर्तमान रूप में उप-धारा (5) को धारा 5 (सी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

1 अप्रैल, 1973 से प्रभावी केंद्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम No.61)।1958 की प्रतिस्थापित उप-धारा के तहत, राज्य

डी.

सरकार केवल वस्तुओं के किसी भी वर्ग या वर्गों के संदर्भ में कर से छूट या कर की दर में कमी दे सकती है, नई प्रतिस्थापित उप-धारा में व्यक्तियों के संदर्भ में भी ऐसी छूट या कटौती का प्रावधान है।खंड 5 (ग) पर टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैंः

द.

"2. विधेयक के खंड 5 का उपखंड 9 (सी) एक नए खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

ई.

मूल अधिनियम की धारा 8 की मौजूदा उप-धारा (5) के लिए धारा राज्य सरकारों को केवल वर्तमान में किसी भी वस्तु या माल के वर्गों के संदर्भ में कर की दर से छूट या कमी देने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से है, लेकिन व्यक्तियों के संदर्भ में भी।द.

कर से छूट या कर की दर में कमी केवल तभी दी जा सकती है जब राज्य सरकार संतुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है।चूंकि उन मामलों की पहले से कल्पना करना संभव नहीं है जिनमें इस तरह की छूट या कटौती आवश्यक हो सकती है और चूंकि छूट और कटौती केवल सार्वजनिक हित में दी जा सकती है, इसलिए छूट या कटौती देने की शक्ति का हस्तांतरण एक सामान्य प्रकृति का है।

च

जी.

अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत 12 मार्च, 1997 को जारी की गई विवादित अधिसूचना इस प्रकार हैः

" एस. ओ. 320-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-4 (8)/एफ. डी./जी. आर. IV/94-70 दिनांक 7 मार्च के स्थान पर,

एच श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।लिमिटेड।वी.राज्य [किरपाल, जे.] 439 1994 (समय-समय पर संशोधित), राज्य सरकार को यह आश्वासन देते हुए कि राज्य में अपना व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यापारी द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान ऐसे किसी भी स्थान से किए गए सीमेंट की बिक्री के संबंध में उक्त धारा की उप-धारा (1) और (2) के तहत देय कर की गणना की जाएगी।

1

निम्नलिखित शर्तों के अधीन 4 प्रतिशत की दर सेः

( 1 ) कि विक्रेता ऐसी अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए बिल या नकद ज्ञापन में खरीदार का नाम और पूरा पता दर्ज करेगा।

उसके द्वारा जारी किया जाना;

( 2 ) कि यह साबित करने का भार कि लेन-देन अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति का था, विक्रेता पर होगा; और (3) कि इस अधिसूचना के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री करने वाला विक्रेता

द्वारा प्रदत्त लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा

अधिसूचना संख्या एफ-4 (72)/एफ. डी./जी. आर. IV/81-18 दिनांक 6.5.86 यथा संशोधित

समय-समय पर।

डी.

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1998 तक लागू रहेगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री.वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने कहा कि धारा 8 (5) के तहत जारी की गई विवादित अधिसूचना केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में निहित विधायी नीति के साथ असंगत थी

}

चूंकि अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर को राज्य के भीतर बेचे जाने पर उक्त माल पर कर की दर से कम कर दिया गया है और इसके अलावा धारा 8 (4) द्वारा विचार किए गए प्रपत्र-सी में घोषणा या प्रपत्र-डी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।उन्होंने आगे कहा कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह लोगों की स्वतंत्र आवाजाही को रोकती है या बाधित करती है।

ई.

एक राज्य से दूसरे राज्य में माल।इस विवाद के समर्थन में भारतीय सीमेंट और अन्य के मामले में उनके द्वारा एफ पर निर्भरता रखी गई थी।वी.आंध्र राज्य

प्रदेश और ओआरएस।, [ 1988 ] 1 एस. सी. सी. 743 और याचिकाकर्ता के अपने मामले में श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी और अन्य।वी.राजस्थान राज्य और अन्य।, [ 1997 ] 5 एससीसी 406।उन्होंने मद्रास राज्य बनाम के मामले में हेगड़े, जे. के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।एन. के. नटराज मुदलियार, [1968] 3 * एस. सी. आर. 829 ने प्रस्तुत किया कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर को जिस तरह से कम किया गया है, वह अनुज्ञेय नहीं है।अंत में उन्होंने आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 8 (5) द्वारा विचारित जनहित की प्रकृति उस तरह की नहीं थी जिसके आधार पर सरकार द्वारा विवादित अधिसूचना जारी की गई है।

जी.

राजस्थान।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रपत्र-सी और डी प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके राजस्थान राज्य ने वास्तव में या तो एच को प्रोत्साहित किया था।

1 440

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

एक सुविधाजनक कर चोरी और इसकी अनुमति नहीं थी और इसे अधिनियम की धारा 8 (5) द्वारा विचार किए गए सार्वजनिक हित में नहीं माना जा सकता था।प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना जनहित में जारी की गई थी और यह संविधान के भाग XIII का उल्लंघन नहीं थी।यह भी उनका निवेदन था कि भारतीय सीमेंट (ऊपर) और श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय बी सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।यह भी उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता जो गुजरात राज्य में एक व्यापारी था, उसके पास राजस्थान राज्य द्वारा जारी विवादित अधिसूचना को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।

.ग

हम जो विचार ले रहे हैं, उसके लिए हम लोकस स्टैंडी के इस प्रश्न पर निर्णय लेने का इरादा नहीं रखते हैं और हम इस मामले में उठाए गए मुद्दों की जांच इस धारणा पर करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका बनाए रखने योग्य है।

डी.

धारा 8 के पढ़ने से संकेत मिलता है कि शुल्क लगाने की योजना

अंतर-राज्यीय बिक्री से संबंधित केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 निम्नलिखित के अंतर्गत आता हैः

पाँच श्रेणियाँः

( 1 )धारा 8 (3) में निर्दिष्ट वस्तुओं के विवरण की सरकार या पंजीकृत विक्रेता को विक्रेता द्वारा अंतर-राज्यीय बिक्री।

ई.

4 प्रतिशत होगा बशर्ते धारा 8 (4) में निर्धारित शर्तें पूरी हों (धारा 8 (1))।

( II) "घोषित वस्तुओं" की धारा 8 (1) के तहत नहीं आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री के अपने कारोबार पर एक व्यापारी द्वारा देय कर, राज्य के भीतर ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लागू दर से दोगुना होगा।

च

उपयुक्त राज्य (धारा 8 (2) (ए))।

( 3. घोषित वस्तुओं के अलावा और धारा 8 (1) के तहत नहीं आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री से संबंधित देय कर दस प्रतिशत या उपयुक्त राज्य के भीतर बिक्री के लिए लागू दर पर होगा।

जो भी अधिक हो (धारा 8 (2) (बी))।

जी.

( IV) धारा 8 (1) या 8 (2) (बी) में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, यदि

जिन वस्तुओं को अंतर-राज्य में बेचा जाता है, जिनकी बिक्री या खरीद, उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के तहत आम तौर पर कर से छूट प्राप्त है या आम तौर पर 4 प्रतिशत से कम दर पर कर के अधीन है, उन्हें या तो कर से छूट प्राप्त होगी या इसके तहत कर से छूट प्राप्त होगी।

एच.

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम कम दर पर लगाया जाएगा क्योंकि यह श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी है।

लिमिटेड।वी.राज्य [किरपाल।जे.] 441 'राज्य' में प्राप्त (धारा 8 (2 ए))।

क.

( V) संविधान की धारा 8 (1) से 8 (4) में कुछ भी निहित होने के बावजूद

अधिनियम, राज्य सरकार, लोक हित में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, किसी भी व्यक्ति को अंतर-राज्य बिक्री के संबंध में कर के भुगतान से छूट दे सकती है, या धारा 8 (1) या 8 (2) (धारा 8 (5)) में निर्दिष्ट दर से कम दर लगा सकती है।बी धारा 8 (5) राज्य सरकार को जनहित में धारा 8 (4) की आवश्यकता को समाप्त करने का अधिकार देती है। एस.

धारा 8 की उप-धाराओं (2), (2 ए) और (5) की वैधता पर विचार किया गया

मद्रास राज्य बनाम में इस न्यायालय के समक्ष विचार।एन. के. नटराज मुदलियार, [1968] 3 एस. सी. आर. 829।उस मामले में प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सी का सफलतापूर्वक प्रतिवाद किया था कि धारा 8 की उप-धाराएं (2), (2 ए) और (5) समान अंतर-राज्य लेनदेन पर विभिन्न राज्यों में कर की अलग-अलग दरों को लागू या अधिकृत करती हैं और इसके परिणामस्वरूप कर के बोझ में असमानता प्रभावित होती है और अंतर-राज्य व्यापार, वाणिज्य और अंतर-पाठ्यक्रम को बाधित करती है जिससे संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 (1) को ठेस पहुंचती है।

डी.

शाह।जे., जैसा कि वे तब थे, का उल्लेख करने के बाद बहुमत के लिए बोल रहे थे

अतिबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का पूर्व निर्णय।असम राज्य और अन्य।, [ 1961 ] 1 एस. सी. आर. 809, फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कं.मद्रास और अन्न राज्य।, [ 1963 ] सप.2 एस. सी. आर. 435; ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनामराजस्थान राज्य और अन्य।, [ 1963 ] 1 अनुच्छेद 301 और ई 303 से संबंधित एस. सी. आर. 491 ने कहा कि यह तय किया गया कानून था कि कोई कर कुछ मामलों में व्यापार के प्रवाह को प्रतिबंधित या बाधित कर सकता है, लेकिन कर का प्रत्येक अधिरोपण ऐसा नहीं करता है।अंतर-राज्यीय बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर अपने सार में एक ऐसा कर था जो व्यापार और वाणिज्य की आवाजाही को बाधित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 303 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न केवल एक राज्य में बल्कि भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में भी लगाया जा सकता है।इस तर्क से निपटते हुए, जिसने उच्च न्यायालय का समर्थन किया था कि विभिन्न राज्यों द्वारा एक ही या समान वस्तु की बिक्री पर कर की दरें अपने आप में भेदभावपूर्ण थीं क्योंकि इसने अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य पर बोझ डालने को अधिकृत किया था और राज्यों के बीच इसके मुक्त प्रवाह को प्रभावित किया था, न्यायाधीश शाह ने पृष्ठ 843 पर आगे कहाः

जी.

" हम उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।व्यापार का प्रवाह आवश्यक रूप से बिक्री कर की दरों पर निर्भर नहीं करता हैःयह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपूर्ति का स्रोत, उपभोग का स्थान, व्यापार चैनलों का अस्तित्व, माल ढुलाई की दरें, व्यापारिक सुविधाएं, कुशल परिवहन की उपलब्धता और अन्य सुविधाएं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

क.

व्यापार करने के लिए।मामलों की आसानी से कल्पना की जा सकती है

जो देश के किसी विशेष भाग में कर की कम दर के बावजूद माल को दूसरे भाग से खरीदा जा सकता है, जहां कर की उच्च दर प्रचलित है।मान लीजिए कि किसी विशेष राज्य में किसी विशेष वस्तु के संबंध में कर की दर 2 प्रतिशत है, लेकिन यदि उस कम दर के लाभ की भरपाई माल ढुलाई द्वारा की जाती है, जिसे किसी अन्य राज्य के व्यापारी को उस वस्तु को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए भुगतान करना पड़ सकता है।

व्यापारी निकटवर्ती राज्य से माल खरीदने के लिए तैयार होगा, भले ही उस राज्य में कर की दर अधिक हो।लंबे समय से चले आ रहे व्यावसायिक संबंधों का अस्तित्व, संचार की उपलब्धता, ऋण सुविधाएं और कई अन्य कारक-स्वाभाविक और व्यावसायिक-व्यापार संबंधों के रखरखाव में प्रवेश करते हैं और व्यापार का मुक्त प्रवाह नहीं हो सकता है।

एस.

अनिवार्य रूप से यह माना जाता है कि केवल इसलिए बाधित किया गया है क्योंकि किसी विशेष राज्य में बिक्री पर कर की दर अन्य राज्यों में प्रचलित दरों से अधिक है।

पुनः पृष्ठ 845 पर यह निम्नानुसार देखा गयाः

डी.

" किसी विशेष वस्तु में अंतरराज्यीय लेन-देन के संबंध में राज्य विधानमंडल जो दर लगाता है, वह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।किसी राज्य को किसी वस्तु पर उच्च दर का कर लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है या तो जब उसका राज्य के भीतर बिल्कुल भी उपभोग नहीं किया जाता है, या यदि उसे लगता है कि राज्य के भीतर उपभोक्ताओं पर जो बोझ पड़ रहा है, वह अंततः बाहरी उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व लाभ से अधिक होगा।बिक्री कर की दरों का अधिरोपण आम तौर पर राजनीतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है।यदि दर इतनी अधिक है कि संभावित व्यापारियों को खरीदारी करने से रोका जा सके।

ई.

वस्तु और आपूर्ति के अन्य स्रोतों का सहारा लेने के लिए राज्य अपने हित में खरीदारों को आकर्षित करने के लिए दर को समायोजित करेगा।एक बार फिर, एक लोकतांत्रिक संविधान में राजनीतिक ताकतें कर की अत्यधिक उच्च दर के खिलाफ काम करेंगी।किसी वस्तु की बिक्री पर कर की दर आम तौर पर मनमाने विचारों पर आधारित नहीं हो सकती है, लेकिन किसी विशेष वस्तु में व्यापार की सुविधा, बाजार की आंतरिक और बाहरी स्थितियों और उपभोक्ताओं के कीमत से डरने की संभावना के आलोक में, जिसमें कर की उच्च दर शामिल है।धारा 8 की उप-धारा (5) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो राज्य सरकार को, धारा 8 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जनहित में कर माफ करने या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य पर कम दर पर बिक्री पर कर लगाने के लिए अधिकृत करती है।यह स्पष्ट है कि विधायिका ने विचार किया है कि दरों की लोच इसके अनुरूप है

च

जी.

एच श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।लिमिटेड।वी.राज्य [किरपाल, जे.) 443

आर्थिक शक्तियों को बनाए रखा जा सकता है।

क.

न्यायालय ने तदनुसार धारा 8 (2), 8 (2 ए) और 8 (5) की वैधता को बरकरार रखा और

पृष्ठ 846 पर निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधिकार के तहत अधिनियमित किया गया है

संघ संसद, लेकिन कर बी राज्य की एजेंसी के माध्यम से एकत्र किया जाता है और अंततः राज्यों के लाभ के लिए लगाया जाता है और वैधानिक रूप से राज्यों को सौंपा जाता है।संविधान द्वारा किए गए संशोधनों से यह स्पष्ट है।( छठा संशोधन) अधिनियम, 1956, Art.269 में, और सी. एल. एस. का अधिनियमन।( 1 ) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 का (4)।केंद्रीय बिक्री कर हालांकि केंद्र सरकार के नाम पर लगाया और एकत्र किया जाता है, बिक्री-कर का एक हिस्सा है जो राज्यों के लाभ के लिए लगाया जाता है।अंतर-राज्यीय लेन-देन पर किसी वस्तु के संबंध में बिक्री कर लगाने के लिए इसे राज्यों पर छोड़ कर

भेदभाव का अभ्यास किया जाता हैःऔर उस राज्य को प्राधिकृत करके जिससे

एक्स

वस्तुओं की आवाजाही बिक्री के लेन-देन पर लगाने के लिए शुरू होती है केंद्रीय बिक्री-कर, राज्य में प्रचलित दरों पर, पहले से ही निर्धारित सीमा डी के अधीन, हमारे निर्णय में, कोई भेदभाव नहीं माना जा सकता है।

हेगड़े, जे. ने एक अलग निर्णय दिया जिसमें शाह, जे. द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि धारा 8 की उपरोक्त उप-धाराएं संविधान के अंतर्गत थीं, लेकिन उस ई निष्कर्ष पर आने के उनके कारण, हालांकि, वही नहीं थे जो बहुमत के साथ प्रबल थे। न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा कि एक बार यह दिखाया जाता है कि एक उपाय प्रथम दृष्टया एक राज्य के निवासियों को दूसरे राज्य पर वरीयता देता है या यह विभिन्न राज्यों में कर की विभिन्न दरों को अपनाने के कारण एक राज्य के निवासियों और दूसरे राज्य के निवासियों के बीच भेदभाव करता है, तो अनुच्छेद 303 (1) को देखते हुए मामला एक अलग रंग धारण करता है।कराधान जाँच समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करने के बाद, उन्होंने पृष्ठ 853 पर कहा कि "इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम एक अव्यवस्थित विधान नहीं है; यह मामले के विभिन्न पहलुओं की गहरी सोच और स्पष्ट विश्लेषण का परिणाम है।यह न्यायालय इस तरह के उपाय को सार्वजनिक रूप से न होने के रूप में रखने में धीमा होगा।

च

ब्याज या अनुच्छेद 303 (1) का उल्लंघन है।विद्वान न्यायाधीश ने तब धारा 8 की विभिन्न उप-धाराओं के प्रावधानों का विश्लेषण किया जो विवादित थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे इंट्रा-वायरस थे और पृष्ठ 856 पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गएः

" अगर हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर राज्यों के लाभ के लिए लगाया जाता है और आगे यह तथ्य कि प्रत्येक एच 444

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

क.

अपने हित में राज्य सरकारों का गठन करने के लिए बाध्य है

उस राज्य में उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए सर्वोत्तम संभव स्थिति, यह मान लेना उचित है कि वे आर्थिक ताकतों के प्रति अंधे नहीं होंगे।जिस चीज से बचना है वह यह है कि वे अपनी कराधान शक्ति का सहारा लेकर अपने राज्य में व्यापार के प्रवाह में बाधा न डालें।सामान्य तौर पर वे यह देखने में रुचि रखेंगे कि उनके राज्यों में उत्पादित वस्तुओं को बाहर बेचा जाए।

अधिनियम के प्रावधानों द्वारा किसी राज्य में व्यापार के मुक्त प्रवाह के खिलाफ उचित रूप से पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, पहला, उस राज्य में बिक्री कर लगाने का प्रावधान करके जिसमें माल का उत्पादन किया जाता है, और दूसरा, दरों को तय करने में राज्यों की शक्ति पर विभिन्न प्रतिबंध लगाकर।किसी ने कोई आपत्ति नहीं की

एस.

प्रावधानों का, मेरी राय में, अंतर पर प्रत्यक्ष या तत्काल प्रभाव पड़ता है।

राज्य व्यापार या वाणिज्य।]}

एन. के. नटराज मुदलियार के मामले में उपरोक्त निर्णय (ऊपर) नहीं

केवल धारा 8 (2) (2 ए) और (5) की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि धारा 8 की उप-धारा (5) ने राज्य सरकार को धारा 8 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सार्वजनिक हित में कर की दर को माफ करने या कम करने के लिए अधिकृत किया।इसलिए, धारा 8 (5) के तहत शक्ति के प्रयोग को इस आधार के अलावा कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इस तरह की शक्ति का उपयोग जनहित में नहीं किया गया है।

ई.

तमिलनाडु राज्य में और अन्य।वी.सीतालक्ष्मी मिल्स और ओआरएस।, [ 1974 ]

4 एस. सी. सी. 408, अधिनियम की धारा 8 (2) (बी) की वैधता पर एक बार फिर इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 301 और 303 के आलोक में विचार किया गया।धारा 8 (2) (बी) की वैधता को बरकरार रखते हुए और एन. के. नटराज मुदलियार (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का पालन करते हुए, इस न्यायालय ने पृष्ठ 414 पर निम्नलिखित टिप्पणी कीः

च

" जहां तक इस तर्क का संबंध है कि धारा 8 (2) (बी) अनुच्छेद 303 (1) का उल्लंघन करती है कि विभिन्न राज्यों में अंतर-राज्य बिक्री पर कर की अलग-अलग दरें होंगी जो अंतर-राज्य बिक्री के लिए उनकी बिक्री कर की दरों के आधार पर होंगी और जिससे समान या समान वस्तुओं की बिक्री पर अलग-अलग कर लगाया जाएगा, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि

जी.

इस न्यायालय द्वारा मद्रास राज्य बनाम में प्रश्न पर विचार किया गया है।एन. के. नटराज मुदलियार (ऊपर) और न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है।अदालत ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में एक ही या समान वस्तु की बिक्री पर कर की अलग-अलग दरों का अस्तित्व भेदभावपूर्ण नहीं होगा क्योंकि व्यापार का प्रवाह आवश्यक रूप से निर्भर नहीं करता है

एच.

बिक्री कर की दरों पर; यह न्यायालय के अनुसार निर्भर करता है -

टी श्री दिग्विजय सीमेंट कं.लिमिटेड।वी.राज्य (किरपाल, जे.) 445 विभिन्न प्रकार के कारक जैसे आपूर्ति का स्रोत, उपभोग का स्थान, व्यापार चैनलों का अस्तित्व, माल ढुलाई की दरें, व्यापारिक सुविधाएं, कुशल परिवहन की उपलब्धता और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सुविधाएं।

अधिनियम की धारा 8 (2) (बी) की वैधता, इस आधार पर कि यह अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है, पर भी ग्वालियर रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. में इस न्यायालय की संविधान बी पीठ द्वारा विचार किया गया था।( डब्ल्यूवीजी.) कं. लिमिटेड बनाम।सहायक बिक्री कर आयुक्त और अन्य।, [ 1974 ] 4 एस. सी. सी. 98 और यह अभिनिर्धारित किया गया कि संसद ने अधिनियम बनाकर अपने विधायी कार्य का त्याग नहीं किया था

अधिनियम की धारा 8 (2) ((बी)।+ वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.लिमिटेड और एक अन्य वी।पंजाब राज्य और सी

एक अन्य, [1990] 3 एस. सी. सी. 87, चुनौती यू. पी. राज्य द्वारा यू. पी. बिक्री कर अधिनियम की धारा 4-ए और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत जारी अधिसूचनाओं के लिए थी, जिसमें निर्माताओं की नई इकाइयों को 3 से 7 साल तक की अलग-अलग अवधि के लिए किसी भी बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी।याचिकाकर्ता, जो नए डी निर्माता नहीं थे और उक्त अधिसूचनाओं के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं थे,

उन्होंने तर्क दिया था कि संविधान के भाग XIII में एक आर्थिक इकाई के रूप में भारत की एकता को बनाए रखने की परिकल्पना की गई थी और इसलिए पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह की गारंटी दी गई थी और इसलिए, किसी भी राज्य को सभी वस्तुओं को छूट देनी चाहिए, भले ही वे स्थानीय रूप से निर्मित हों या अन्य राज्यों से आयात किए गए हों, अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 304 और 304 (ए) का उल्लंघन होगा।इस तर्क को खारिज करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य दर को बराबर बनाए रखते हुए, कुछ उद्योगों के लिए सीमित अवधि के लिए विशेष दरें राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 (ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना निर्धारित की जा सकती हैं।इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए पृष्ठ 108 पर निम्नलिखित देखा गयाः

च

" आर्थिक बाधा की अवधारणा को बदलती परिस्थितियों के साथ गतिशील अर्थों में अपनाया जाना चाहिए।एक समय में जो आर्थिक बाधा बनती है, वह अक्सर दूसरे समय में समाप्त हो जाती है।संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में विधायी प्रमुखों की पूर्ण शक्तियों से निकलने वाली छूट देने के अधिकार से राज्य के लोगों को वंचित करना गलत होगा।संघीय राजनीति में, सभी राज्यों को सीमित अवधि के लिए निर्दिष्ट वर्ग को छूट देने की शक्ति है, इस तरह की छूट को आर्थिक एकता की अवधारणा के

विपरीत नहीं माना जा सकता है।भारत के लोगों द्वारा आर्थिक एकता की सामग्री (एस. आई. सी. अवधारणा) में अनिवार्य रूप से एच में छूट देने या कर की दर को कम करने की शक्ति शामिल होगी।

जी 446।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1999] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

क.

औद्योगिक विकास प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए विशेष मामले

विकास और विकास में आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए कर प्रोत्साहन।जब सभी राज्यों के पास दरों को छूट देने या कम करने के लिए ऐसे प्रावधान होते हैं तो राज्यों के बीच आर्थिक युद्ध या देश के आर्थिक विघटन का सवाल ही पैदा नहीं होता है।यह किसी भी पक्ष के लिए यह कहने के लिए खुला नहीं है कि यह किया जाना चाहिए और यह किसी एक या दूसरे तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्यों को कर वसूल करने और उसके बाद उसे भेजने या स्थानीय निर्माताओं को सब्सिडी के रूप में वापस करने का अधिकार है और यह न तो भेदभाव करेगा और न ही अनुच्छेद 304 (ए) से प्रभावित होगा।

वी '

संविधान।इस मामले में और सभी संवैधानिक निर्णयों की तरह मामले के सार पर यह पता लगाने के लिए गौर किया जाना चाहिए कि क्या

एस.

संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन में कोई भेदभाव है "।

अधिनियम की धारा 8 (5), जिसे वैध माना गया है और जिसका

पूर्व-कथित निर्णयों में परिधि की व्याख्या की गई है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य में व्यवसाय का स्थान डी रखने वाले किसी भी व्यापारी द्वारा कुछ प्रकार की वस्तुओं की अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में, कोई कर देय नहीं होगा या कर की गणना उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दरों से कम दरों पर की जाएगी।वर्तमान मामले में सीमेंट जैसी कुछ प्रकार की वस्तुओं पर अंतर-राज्य बिक्री कर की दर को छूट देने या कम करने की इस शक्ति का उपयोग निश्चित रूप से तब किया जाना चाहिए जब राज्य सरकार संतुष्ट हो कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 8 जनवरी, 1990 की अधिसूचना के माध्यम से कर को घटाकर 7 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप, उसे उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में लाखों रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला था।जवाब में हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जब तक राजस्थान राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तब तक राज्य का आगे का आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास बाधित होगा।राज्य में सीमेंट का उत्पादन खपत से कहीं अधिक एफ था।सीमेंट निर्माताओं के पास उपलब्ध अधिशेष को राज्य के बाहर बेचना पड़ता था और जब तक सीमेंट निर्माण इकाइयों के लिए राज्य के बाहर अपना सीमेंट बेचना फायदेमंद नहीं होता, तब तक राज्य के भीतर सीमेंट उद्योग पंगु हो जाएगा जिसका राजस्थान राज्य पर प्रतिकूल औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।कर की उच्च दर

जी.

अंतर-राज्यीय बिक्री जो प्रचलित थी, उसके परिणामस्वरूप विनिर्माण इकाइयों को बिना सीमेंट के एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमेंट की शाखा हस्तांतरण का सहारा लेना पड़ा।

राजस्थान राज्य में किसी भी कर का भुगतान करने और अंतर-राज्य बिक्री कर को कम करने से कर संग्रह में वृद्धि हुई।राजस्थान में 33 इकाइयाँ थीं जो सीमेंट के निर्माण में लगी हुई थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि एच 10475 कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा था।इसके अलावा,

25000 श्रमिकों को खनन उद्योग में लगे हुए बताया गया था और 50,000 से अधिक श्रमिक संबद्ध गतिविधियों जैसे परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग और मार्केटिंग आदि में लगे हुए थे। राजस्थान राज्य में सीमेंट की मांग सीमित होने के कारण, राजस्थान राज्य से सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री को प्रोत्साहित करना अनिवार्य हो गया।अंतर-राज्यीय बिक्री कर की दर को कम करने से उच्च कर रिटर्न में सुविधा हुई और उद्योग में बी कार्य जारी रहा।इससे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उक्त अधिसूचना जारी करना जनहित में था जैसा कि अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा परिकल्पित है।हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि विवादित अधिसूचना का एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की मुक्त आवाजाही को रोकने या बाधित करने का प्रभाव था।जहाँ तक एस

राजस्थान राज्य की बात करें तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ा।सिर्फ इसलिए कि

गुजरात राज्य में सीमेंट की बिक्री पर कर की स्थानीय दर राजस्थान से बेचे जाने वाले सीमेंट पर अंतर-राज्य बिक्री कर से अधिक थी, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि विवादित अधिसूचना ने सीमेंट की बिक्री को रोका या बाधित किया।

एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही।वास्तव में आक्षेपित अधिसूचना

इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, अर्थात्, इसने डी राजस्थान से अन्य राज्यों में सीमेंट की आवाजाही को बढ़ाया।ऐसा नहीं है कि विवादित अधिसूचना ने एक बाधा उत्पन्न की है जिसका माल की मुक्त आवाजाही में बाधा डालने का प्रभाव हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर, बिक्री कर बाधा को कम कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि हुई थी।

अंतर-राज्यीय व्यापार की मात्रा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 8 फर्निशिंग ई पर विचार करती है।

प्रपत्र-सी और प्रपत्र-डी जहां अंतर-राज्यीय बिक्री पंजीकृत विक्रेता या राज्य के बाहर सरकारी विभाग को की जाती है।लेकिन एक अधिसूचना जो धारा 8 की उप-धारा (5) के तहत जारी की जाती है, गैर-अवरोधक खंड को देखते हुए एक प्रबल प्रभाव डाल सकती है।प्रपत्र-सी और प्रपत्र-डी को राजस्थान के विक्रेताओं द्वारा पंजीकृत विक्रेता एफ को की जा रही अंतर-राज्यीय बिक्री का प्रमाण माना जाता है।

या राजस्थान के बाहर किसी सरकारी विभाग में।विवादित अधिसूचना में विक्रेता को बिल या नकद ज्ञापन पर खरीदार का नाम और पता दर्ज करना होता है जिसे उसे अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में जारी करना होता है और विक्रेता को यह साबित करना होता है कि लेन-देन अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति का था।हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि फॉर्म-सी और फॉर्म-डी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के प्रतिस्थापन के लिए जी डीलर को बिल या नकद ज्ञापन में खरीदार का नाम और पता दर्ज करना अनिवार्य बनाने से कर चोरी में सुविधा होगी।राजस्थान राज्य का अनुभव रहा है कि इस तरह की अधिसूचनाओं के जारी होने से सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री पर उसके कर राजस्व में वृद्धि हुई है।

श्री शांति भूषण ने इस एच के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया था



भारतीय सीमेंट (ऊपर) के मामले में एक न्यायालय।यह न्यायालय उस मामले पर विचार कर रहा था जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य ने अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत उस राज्य से अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री के संबंध में कर की दर को कम करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।अतियाबारी टी कंपनी में इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करने के बाद। लिमिटेड, एन. के. नटराज मुदलियार,

ग्वालियर रेयॉन रेशम निर्माण (डब्ल्यू. वी. जी.) कं. लिमिटेड और सीतालक्ष्मी मिल्स

( ऊपर), इस न्यायालय ने पृष्ठ 759 पर निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" अंतर-राज्यीय बिक्री कर की दर में बदलाव से मुक्त व्यापार प्रभावित नहीं होता है

और वाणिज्य और एक स्थानीय वरीयता पैदा करता है जो इसके विपरीत है

संविधान के भाग XIII की योजना।अधिसूचना का विस्तार है

अपंजीकृत विक्रेताओं और हेगड़े की टिप्पणियों को भी लाभ,

एस.

जे. मामले के इस पहलू पर प्रासंगिक हैं।दोनों अधिसूचनाएँ

इसलिए, आंध्र प्रदेश सरकार खराब है और इससे प्रभावित है

संविधान के भाग XIII के प्रावधान।इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।

कानून में "।

उपरोक्त निष्कर्ष, संबंध के साथ, के निर्णयों से नहीं आता है

डी.

इस न्यायालय की संविधान पीठ जिनका संदर्भ दिया गया है

इससे पहले।अंतर-राज्यीय बिक्री कर की दर में भिन्नता की स्पष्ट रूप से अनुमति है

अधिनियम की धारा 8 (5) जिसकी वैधता को एन. के. में स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया है।

नटरजा मुदलियार मामला (ऊपर)।यह भारतीय में निष्कर्ष है

सीमेंट मामला (ऊपर) अंतर-राज्य बिक्री कर की दर में परिवर्तन, जो

ई एक स्थानीय वरीयता बनाता है, भाग XIII की योजना के विपरीत है

संविधान सही नहीं है।भारतीय सीमेंट मामले (ऊपर) में संदर्भ है

हेगड़े, जे. की टिप्पणियों के लिए जो निम्नलिखित प्रभाव वाले थे।

" धारा 8 की उप-धारा (5) व्यक्तिगत छूट देने का प्रावधान करती है।

जनहित में।इस तरह की शक्ति सभी कराधान उपायों में है।यह है।

अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करना।उदाहरण के लिए, जब वहाँ

च

बिहार में अकाल था, अगर पंजाब में किसी व्यापारी ने माल बेचने का बीड़ा उठाया होता

उस राज्य में एक धर्मार्थ संस्था को वितरण के लिए उचित मूल्य पर

जो लोग भूखे थे, उनके लिए यह जनहित में होता अगर

पंजाब सरकार ने उस डीलर को बिक्री का भुगतान करने से छूट दी थी।

कर।ऐसी शक्ति मुक्त प्रवाह को तुरंत या सीधे प्रभावित नहीं कर सकती है।

व्यापार से।विचाराधीन शक्ति को खराब नहीं कहा जा सकता है।अगर ऐसा है तो

उस शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को चुनौती दी जा सकती है।

"

हम एन. के. नटराज में हेगड़े, जे. की ये टिप्पणियाँ नहीं पाते हैं।

मुदलियार मामला (ऊपर) किसी भी तरह से इंगित करता है कि सार्वजनिक हित में दर

अंतर-राज्यीय बिक्री कर को कम नहीं किया जा सकता था, भले ही इसका मतलब लाभ हो।

एच गैर-पंजीकृत विक्रेता को दिया जाता है।दूसरी ओर छूट देने की शक्ति टी श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।

लिमिटेड।वी.स्टेट (किरपाल, जे.) 449 को बरकरार रखा गया था बशर्ते इसका दुरुपयोग न किया गया हो।हम तदनुसार मानते हैं कि भारतीय ए सीमेंट मामले (उपरोक्त) का सही निर्णय नहीं लिया गया है और तदनुसार, खारिज कर दिया गया है।

श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी मामले (उपरोक्त) में, राजस्थान राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, अधिनियम की धारा 8 (5) द्वारा विचारित जनहित का अर्थ होगा -

राजस्थान की जनता के हित में और चूंकि बढ़े हुए राजस्व का उपयोग राजस्थान के लोगों के लाभ के लिए किया जा सकता है, इसलिए सत्ता के विवादित प्रयोग को जनहित में माना जाना चाहिए।इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया और यह देखा गया कि सार्वजनिक हित की व्याख्या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 के संदर्भ में की जानी चाहिए।आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि राजस्व में वृद्धि और राज्य की जनता के लिए इसके उपयोग को आम तौर पर लोक हित में माना जा सकता है, लेकिन यदि यह अधिनियम की नीति और संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य के खिलाफ जाने का प्रभाव रखता है, तो इसे अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 8 (5) स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को अंतर-राज्य बिक्री कर की दर को कम करने में सक्षम बनाती है यदि वे संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।1957 से पहले, धारा 8 की उप-धारा (5) ने केंद्र सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक हित में बिक्री कर की दर को कम करने की शक्ति दी थी।केंद्रीय बिक्री कर संशोधन अधिनियम, 1957 के साथ, संसद ने केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की।इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ई में अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट लोक हित में निश्चित रूप से संबंधित राज्य का लोक हित शामिल होगा।यदि कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप राजस्व और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे उद्योग के साथ-साथ चूना पत्थर के खनन में भी रोजगार मिलता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिसूचना जनहित में जारी नहीं की गई थी।

एफ.

च

श्री दिग्विजय सीमेंट मामले (उपरोक्त) में उपरोक्त निर्णय में यह भी कहा गया था कि प्रपत्र-सी में घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में विचार करते हुए, यह समझना मुश्किल था कि राजस्थान राज्य कैसे कर के भुगतान या सीमेंट की अंतर-राज्यीय बिक्री की चोरी को प्रभावी ढंग से रोक सकता था या रोक सकता था।अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत, राज्य सरकार जी में कुछ भी निहित होने के बावजूद शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

अनुभाग ने कहा।इसलिए, प्रपत्र-सी और प्रपत्र-डी प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 8 की उप-धारा (4) की आवश्यकता के बावजूद, राज्य सरकार कर की दर को कम करते हुए ऐसी शर्तें लगा सकती है जो अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के अनुरूप न हों।जब प्रपत्र-सी और प्रपत्र-डी प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि बिक्री एच है।



अंतर-राज्यीय बिक्री के दौरान राज्य सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अलग तरीका या तरीका प्रदान कर सकती है। तत्काल मामले में, अधिसूचना का लाभ उठाने की शर्त यह है कि

बिल या नकद ज्ञापन में खरीदार का नाम और पूरा पता बताना होता है और इसके परिणामस्वरूप, यह साबित करने का बोझ कि लेन-देन अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति का था, विक्रेता पर होता है।अतः मूल्यांकन के समय,

विक्रेता जो उक्त अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे करना होगा

राज्य के बाहर खरीदार की पहचान स्थापित करना और बदले में,

साबित करें कि एक अंतर-राज्यीय बिक्री हुई है।जो कर एकत्र किया जाता है, वह उस राज्य को आवंटित किया जाता है जहां से माल की आवाजाही शुरू होती है।इसलिए,

इस सवाल को प्रासंगिकता के साथ देखा जाना चाहिए कि क्या कर की चोरी होती है

सी उस राज्य के लिए।यदि कर में कमी के परिणामस्वरूप अधिक लोगों को उस राज्य को कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करके कर संग्रह में वृद्धि होती है तो यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 301 का उल्लंघन किया गया है।

हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि उक्त अधिसूचना को वितरित करके

प्रपत्र-सी में घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता का प्रभाव पड़ा

डी कर के भुगतान की चोरी को सुविधाजनक बनाना और अध्याय XIII में निहित संवैधानिक प्रावधानों की योजना का उल्लंघन था।

श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के मामले (ऊपर) में, यह देखा गया था किः

ई.

" हमारा यह भी विचार है कि राज्य द्वारा दिया गया औचित्य

ई.

राजस्थान का कि विवादित अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप राज्य

राजस्व में वृद्धि हुई थी और इस प्रकार वे राज्य के लिए फायदेमंद थे।

राजस्व, मान्य नहीं है क्योंकि उक्त अधिसूचनाओं का निर्माण का प्रभाव था

आप।

राजस्थान में निर्मित और बेचे जाने वाले सीमेंट को प्राथमिकता देना और

गुजरात में निर्मित और बेचे जाने वाले सीमेंट की बिक्री के लिए नुकसान

और इस प्रकार मुक्त प्रवाह पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

च

व्यापार "।

राजस्थान राज्य द्वारा कर की दर को कम करने का, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, व्यापार के प्रवाह को बढ़ाने का सीधा प्रभाव पड़ा है।केवल यह तथ्य कि गुजरात में सीमेंट की स्थानीय बिक्री प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, इसके परिणामस्वरूप विवादित अधिसूचना को व्यापार के मुक्त प्रवाह को प्रभावित करने वाला नहीं माना जा सकता है।

जी.

और संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है।उक्त प्रावधान एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही से संबंधित है और

जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, कर में कमी के साथ, आवाजाही कम होने के बजाय बढ़ी है।

एच.

श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।

लिमिटेड।वी.स्टेट [किरपाल, जे.] 451 (ऊपर), हमारी राय में, सही कानून निर्धारित नहीं करता है और वही ए है

तदनुसार अधिक शासित।उपर्युक्त कारणों से हम विवादित की वैधता को बरकरार रखते हैं।

राजस्थान राज्य द्वारा 12 मार्च, 1997 को जारी अधिसूचना के परिणामस्वरूप इस रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

पी के एस।